भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3577

जिसका उत्तर 23 मार्च, 2017 को दिया जाना है ।

गांवों का विद्युतीकरण

3577. डॉ. उदित राजः

श्री भगवंत खुबाः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) ग्रामीण विद्युतीकरण की परिभाषा क्या है;

(ख) सरकार द्वारा ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए कौन सी योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं;

(ग) योजना की सफलता का ब्यौरा क्या है तथा चालू वित्त वर्ष के दौरान कितने गांवों का विद्युतीकरण किया गया और देश के सभी राज्यों के विद्युतीकरण हेतु क्या समय-सीमा तय की गई है; और

(घ) क्या सरकार को ऊर्जा, पर्यावरण तथा जल परिषद (सीईईडब्ल्यू) और कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा किए गए अध्ययन की जानकारी है जिसके अनुसार ग्रामीण परिवार, ग्रामीण विद्युतीकरण के मामले में अभी भी पीछे हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : ग्रामीण विद्युतीकरण (आरई) नीति, 2006 के अनुसार, किसी गांव को विद्युतीकृत सूचित किया जाता है, यदि

(i) आधारभूत ढांचे जैसे वितरण ट्रांसफार्मर और वितरण लाइनें बसी हुई स्थानीय आबादी के साथ-साथ समाज के कमजोर वर्गों की बसी हुई स्थानीय आबादी/पुरवों जहां वे विद्यमान हैं, उपलब्ध कराई गई हैं,

(ii) सार्वजनिक स्थानों जैसे स्कूलों, पंचायत घरों, स्वास्थ्य केंद्रों, औषधालयों, सामुदायिक केंद्रों आदि को विद्युत उपलब्ध कराई गई है, तथा

(iii) विद्युतीकृत घरों की संख्या गांव के कुल घरों की संख्या का कम से कम 10% होनी चाहिए।

किसी गांव को राज्यों द्वारा विद्युतीकृत सूचित किया जाता है, जब वह उपरोक्त मानदण्डों को पूरा करता है। तथापि, आधारभूत ढांचे का स्तर उसी गांव के विभिन्न वासस्थलों में पृथक-पृथक हो सकता है।

(ख) : ग्रामीण क्षेत्रों में, कृषि और गैर-कृषि उपभोक्ताओं को आपूर्ति की विवेकपूर्ण रोस्टरिंग की सुविधा प्रदान करके कृषि तथा गैर-कृषि फीडरों को पृथक करने, ग्रामीण क्षेत्रों में उप-पारेषण और वितरण अवसंरचना के सुदृढ़ीकरण एवं सवर्धन जिसमें ग्रामीण विद्युतीकरण और वितरण ट्रांसफार्मरों/फीडरों/उपभोक्ताओं पर मीटरिंग शामिल है, के लिए भारत सरकार ने दिसंबर, 2014 में 43033 करोड़ रूपए के परिव्यय से दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) अनुमोदित की है।

(ग) : राज्यों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार चालू वित्तीय वर्ष (28.02.2017 तक) के दौरान 5256 गांव विद्युतीकृत किए गए हैं। सभी गैर-विद्युतीकृत गांवों को 1 मई, 2018 तक विद्युतीकृत किए जाने का लक्ष्य है।

(घ) : ऊर्जा, पर्यावरण एवं जल परिषद (सीईईडब्ल्यू) ने ऊर्जा पहुंच सर्वेक्षण प्रकाशित किया है। भारत सरकार ने 'सभी के लिए 24x7 विद्युत' उपलब्ध कराने के लिए राज्य विशिष्ट दस्तावेज तैयार करने तथा राज्य नीति के अनुसार कृषि उपभोक्ताओं को पर्याप्त आपूर्ति हेतु राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ एक संयुक्त पहल शुरू की है। आज की तारीख के अनुसार उत्तर प्रदेश को छोड़कर सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने 'सभी के लिए 24x7 विद्युत' के लिए केंद्र सरकार के साथ दस्तावेज हस्ताक्षरित किए हैं।

****